जन पक्षीय नीतियों के लिये और जन विरोधी कार्रवाईयों के खिलाफ

संयुक्त रूप से देश व्यापी लामबंदी की जाए

□ तपन सेन

सीआइटीयू जनरल काऊंसिल की चार दिवसीय बैठक गत 17 से 20 जुलाई तक नासिक में संपन्न हुयी। बैठक ने चुनावी जनादेश का सम्मान करने के लिए केंद्र की यूपीए सरकार की आर्थिक नीतियों को जनपरस्त दिशा देने और मौजूदा बजट में सामने आए जनविरोधी कदमों को वापस लिए जाने की मांग करते हुए मेहनतकश अवाम की जोरदार देशव्यापी जनलामबंदी का आह्वान किया है।

दोहरा काम

सीआइटीयू जनरल काऊंसिल ने दिसंबर 2003 में संपन्न हुए सीआइटीयू के ग्यारहवें सम्मेलन के बाद के घटनाविकास ,जिसमें चुनावी लड़ाई में मजदूर वर्ग की भूमिका भी शामिल है, जिसके चलते सांप्रदायिक शक्तियों के नेतृत्ववाले जनविरोधी एन डी ए निजाम की करारी हार हुयी है,और उसके बाद की स्थिति की समीक्षा करते हुए मजदूर वर्ग के आंदोलन के समक्ष बहुत ही स्पष्ट रूप में उसके काम रखे।

बैठक ने महासचिव की रिपोर्ट में पेश किए गए इस सूत्रीकरण को स्वीकार किया कि ''मौजूदा स्थिति ने सीआइटीयू पर एक विराट काम सौंप दिया है। आम चुनावों में भाजपा गठबंधन की हार और उसकी जगह केंद्र में वामपंथी पार्टियों के बाहरी समर्थन से सत्ता में आयी संप्रग सरकार ने मेहनतकश अवाम में भारी अपेक्षाएं पैदा कर दी हैं। इन अपेक्षाओं को जोरदार अभियान तथा जनलामबंदी के जरिए आर्थिक नीतियों को जनपरस्त दिशा देने और जनतांत्रिक अधिकारों को विस्तार देने की मांग करते हुए जोर-शोर से सामने लाया जाना चाहिए,वरना हताशा पैदा हो जाएगी और मौके के इंतजार में बैठी सांप्रदायिक शक्तियों को लाभ मिलेगा। उदारीकृत नीतियों को जारी रखने को लेकर शासक गठजोड़ में शामिल पार्टियों के वर्गीय चरित्र और चाल-ढ़ाल को देखते हुए, ऐसा नहीं लगता है कि जनता की अधिकतर अपेक्षाएं,जो चुनावी जनादेश में प्रतिबिंबित हुयी हैं,को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलेगी। वर्ष 2004-05 के केंद्रीय बजट ने कुछ सकारात्मक कदमों के बावजूद इस सच्चाई को दिखा दिया है। इस पृष्ठभूमि में मजदूर वर्ग के आंदोलन को, आर्थिक नीतियों को स्पष्ट जनपरस्त दिशा देने की मांग करते हुए और नकारात्मक कदमों का विरोध करते हुए सांप्रदायिक शक्तियों को और ज्यादा अलग-थलग करने के राजनीतिक काम के अभिन्न हिस्से के तौर पर और साथ ही साथ वामपंथ के हस्तक्षेप का रास्ता बनाने और उसे मजबूत करने के लिए जनता को लामबंद करने के काम को अपने कंधों पर लेना होगा। धर्मनिरपेक्ष शासन को बनाए रखने और सांप्रदायिक शक्तियों को अलग-थलग करने के लिए इस तरह के हस्तक्षेप निर्णायक और आवश्यक हैं।''

बैठक की कार्रवाई

सीआइटीयू जनरल काऊंसिल की बैठक 17 जुलाई को स्वागत समिति के अध्यक्ष और नासिक के जाने-माने एडवोकेट जयंत जयभावे के स्वागत भाषण के साथ शुरू हुयी। सीआइटीयू अध्यक्ष एम के पंधे ने अध्यक्षीय भाषण दिया। अपने अध्यक्षीय भाषण में अंतर्राष्ट्रीय घटनाविकास का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हड़तालों,प्रदर्शनों और दूसरी कार्रवाइयों के जरिए साम्राज्यवादी विश्वीकरण की नव उदारवादी नीतियों और गरीबी, भुखमरी, रोजगारहीनता तथा बढ़ती असमानताओं की समस्याओं को संबोधित करने में उनकी पूर्ण विफलता के खिलाफ विश्वव्यापी संगठित विरोध बढ़ता जा रहा है।

उनका कहना था कि ये समस्याएं न केवल विकासशील देशों में बढ़ रही हैं बल्कि विकसित औद्योगीकृत देशों में भी बढ़ रही हैं। अध्यक्षीय भाषण में यह भी नोट किया गया था कि आर्थिक उदारीकरण के साथ ही साथ साम्राज्यवादी शक्तियां किसी न किसी बहाने से बौखलाहट के साथ विकासशील देशों पर आक्रमण कर रही हैं,सैन्य हमले कर रही हैं और दादागिरी कर रही हैं,जैसा कि अफगानिस्तान, इराक, क्यूबा और वास्तव में तो पूरे मध्य-पूर्व ,मध्य एशिया, अफ्रीका और लातीनी अमरीका में ही देखने में आ रहा है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों के दौरान दुनिया भर की जनता जोरदार युद्धविरोधी प्रदर्शनों और अन्य कार्रवाइयों के जरिए अमरीकी साम्राज्यवादी साजिशों के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा मुखर होती जा रही है।

राष्ट्रीय संदर्भ में पंधे का कहना था कि भाजपा निजाम द्वारा लागू की जा रही जनविरोधी और राष्ट्रविरोधी नीतियों के खिलाफ जनता का जनादेश भाजपा निजाम की हार और देश की स्थिति में बदलाव के रूप में प्रतिबिंबित हुआ है। इन नीतियों के खिलाफ मजदूर वर्ग निरंतर तथा एकजुट

संघर्ष चलाता रहा था। इसलिए उनका कहना था कि नयी यूपीए सरकार की नीति ऐसी हो जो पूर्ववर्ती सरकार की नीति से साफ तौर पर अलग हो और इसलिए पंधे ने जोर देकर कहा कि अब नीतियों की दिशा जनपरस्त कदमों तथा आत्मनिर्भरता की ओर होनी चाहिए।

सीआइटीयू महासचिव चित्तब्रत मजूमदार एक दुर्घटना के बाद होनेवाली सर्जरी के चलते इस बैठक में भाग नहीं ले पाए थे। अस्पताल से ही उन्होंने जनरल काऊंसिल के लिए एक संदेश भेजा था जिसमें उन्होंने उन मुद्दों पर जोर दिया था जिन पर बैठक में चर्चा होनी थी।

आम चुनावों में भाजपा के नेतृत्ववाली सरकार की हार का जिक्र करते हुए उन्होंने अपने संदेश में कहा था कि "यहां यह भी उल्लेखनीय है कि हाल के चुनावों में न सिर्फ केंद्र को बल्कि उन राज्य सरकारों को भी करारी हार का मुंह देखना पड़ा है जिन्होंने अपने राज्यों में नव-उदारवादी नीतियां लागू की थी... इसने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि उदारीकरण, निजीकरण तथा विश्वीकरण के आइ एम एफ और विश्व बैंक के दिखाए रास्ते,जो कि जनविरोधी है और साम्राज्यवादी शोषण को प्रतिबिंबित करता है, का शोषित-पीड़ित जनता ने विरोध किया है और आगे भी विरोध करेगी।"

उन्होंने अपने संदेश में नव-उदारवादी साम्राज्यवादी विश्वीकरण और अपने समग्र रूप में पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष जारी रखने की जरूरत पर जोर दिया था जिसके संदर्भ में और जिसकी पृष्ठभूमि में सीआइटीयू को मौजूदा स्थिति में विवेकपूर्ण ढ़ंग से अपनी रणनीति बनानी होगी। उनका कहना था कि हमें मजदूर वर्ग की एकता को मजबूत करना होगा, असंगठित क्षेत्र को विशेष ध्यान देकर संगठित करना होगा, संघर्ष में व्यापक जनता को शामिल करना होगा और मजदूरों तथा किसानों की एकजुटता को पक्का करने पर और ज्यादा जोर देना होगा। चित्तब्रत मजूमदार ने जनरल काऊंसिल को भेजे अपने इस संदेश में दोहराया कि मजदूर वर्ग के आंदोलन की दिशा वर्ग संघर्ष तथा जनतांत्रिक संघर्ष को एक साथ लाने की होनी चाहिए।

सीआइटीयू सचिव कनाई बनर्जी ने बैठक में महासचिव की रिपोर्ट पेश की। उन्होंने आम आदमी और मजदूर वर्ग द्वारा प्रदर्शित किए गए शानदार लचीलेपन की भारी सराहना की,जो आम चुनावों में जनविरोधी तथा राष्ट्रविरोधी एन डी ए गठजोड़ को मात देने के लिए दृढ़निश्चय के साथ लड़े थे। रिपोर्ट में वामपंथी पार्टियों तथा ट्रेड यूनियन आंदोलन द्वारा सांप्रदायिक एन डी ए निजाम के खिलाफ लोगों को चेतन बनाने के लिए अदा की गयी निर्णायक भूमिका को नोट किया गया था और एक तरफ सांप्रदायिक शक्तियों को जनता से और ज्यादा अलग-थलग करने के लिए और दूसरी तरफ आर्थिक नीतियों को जनपरस्त दिशा देने पर दबाव बनाने के लिए उनकी प्रोएक्टिव तथा आग्रही भूमिका को जोरदार ढ़ंग से आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया था।

रिपोर्ट में यूपीए सरकार के राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम की सकारात्मक जनपरस्त वचनबद्धताओं को नोट किया गया था और साथ ही साथ टेलीकोम ,बीमा तथा नागरिक उड्डयन क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में भारी बढ़ोतरी करने,लघु उद्योगों के लिए सूचीबद्ध 85 आइटमों को आरक्षण मुक्त करने और प्रोविडेंट फंड के लिए ब्याज दरों को कम करने के रूप में इस सरकार के पहले ही बजट में सामने आयी नकारात्मक बातों को भी नोट किया गया था।

रिपोर्ट में कहा गया था कि इस पृष्ठभूमि में ट्रेड यूनियन आंदोलन को सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम में की गयी जनपरस्त वचनबद्धताओं को लागू करवाने के लिए जनता को लामबंद करने और मौजूदा बजट में सामने आए नकारात्मक कदमों के खिलाफ जोरदार विरोध का निर्माण करने और साथ ही साथ मेहनतकश जनता की रोजी-रोटी तथा उसके अधिकारों की रक्षा करने के काम अपने हाथ में लेने होंगे। मजदूर वर्ग के आंदोलन के सामने यह एक चुनौती भरा काम है कि वह संप्रग सरकार को जनता से किए गए अपने वादों को पूरा करने और साथ ही साथ सांप्रदायिक शक्तियों का मुकाबला करने के लिए तैयार करे।

इस दिशा में प्रयास पहले ही शुरू हो चुके हैं। मेहनतकश अवाम की चिंताओं के मुद्दों की संयुक्त रूप से पहचान की जा रही है और नीतियों की दिशा बदलने के लिए देशव्यापी एकजुट लामबंदी की योजना बनायी जा रही है।

बहस और समापन

इस रिपोर्ट पर हुयी बहस में कुल मिलाकर 53 सदस्यों ने भाग लिया। उन्होंने आमतौर पर स्थिति में आए बदलाव के निहितार्थों के सिलसिले में मेहनतकश अवाम के व्यापकतम तबकों के बीच सघन देशव्यापी अभियान चलाने और संयुक्त संघर्षों के जरिए सांप्रदायिक ताकतों को अलग-थलग करने और शोषित-पीड़ित जनता के अधिकारों तथा हितों की रक्षा करने के दोहरे काम को अंजाम देने की अपील की। वे मजदूर वर्ग के आंदोलन द्वारा नवउदारवादी साम्राज्यवादी विश्वीकरण की नीतियों के निरंतर विरोध पर एकमत थे।

उनका कहना था कि आर्थिक नीतियों की दिशा में बदलाव के जोरदार एकजुट प्रयास हमारी गतिविधियों का मुख्य आधार होने चाहिए। बैठक को बिरादराना उद्योगवार फेडरेशनों के नेताओं ने भी संबोधित किया।

कनाई बनर्जी ने बहस का समापन करते हुए कहा कि बैठक में हुए विचार-विमर्श ने आमतौर पर बदली हुयी स्थिति तथा हमारे कामों के बारे में संगठन के भीतर की एकजुट समझ को ही प्रतिबिंबित किया है। उन्होंने सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ निरंतर अभियान चलाने के निर्णायक महत्व को रेखांकित किया। उनका कहना था कि संगठन के किसी भी स्तर पर इसमें कोई कोताही नहीं हो सकती ,नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ मेहनतकश अवाम की

रोजी-रोटी और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष चलाने के लिए उसे लामबंद भी करना होगा।

उनका कहना था कि मजदूर वर्ग के आंदोलन द्वारा विश्वीकरण की नव-उदारवादी नीतियों के खिलाफ सामूहिक विचारधारात्मक तथा संगठित आग्रह की निरंतरता की भी फौरी जरूरत है।

बैठक के अपने समापन भाषण में एम के पंधे ने मजदूर वर्ग का आह्वान किया कि वह इस चुनौती को एकजुट रूप में सामना करे। उनका जोर देकर यह कहना था कि विश्वीकरणविरोधी संघर्ष मजदूर वर्ग के एकजुट आंदोलन की जीवन रेखा है और उसे एक वर्ग के रूप में बदलाव के लिए राजनीतिक रूप से हस्तक्षेप करने के काबिल बनाता है।

उन्होंने उन सुधारवादी तथा वर्ग सहयोगवादी विचारों के खिलाफ भी आगाह किया,जिन्हें मेहनतकश अवाम के बीच प्रचारित करने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही साथ उन्होंने पूंजीवादी मीडिया तथा उदारीकरण के प्रचारकों द्वारा विश्वीकरणपरस्त अभियान चलाए जाने के खिलाफ भी सचेत रहने की अपील की। इस तरह का ताजातरीन विचारधारात्मक हमला विश्वीकरण के मौजूदा रूप को सार्वभौम, आवश्यक तथा अपरिवर्तनीय बताने के रूप में चलाया जा रहा है जिसके बारे में उनका तर्क है कि विश्वीकरण के इस रूप का विरोध नहीं किया जाना चाहिए। इसके साथ ही इस हमले के जरिए उदारीकरण को विश्वीकरण से अलग दिखाने की कोशिश की जा रही है और ऐसा प्रचारित किया जा रहा है कि जैसे ये दो अलग फिनोमिना हों।

इस सिलसिले में फिदेल कास्त्रो को उद्धृत करते हुए एम. के पंधे ने कहा कि "हम विश्वीकरण के खिलाफ नहीं हैं,हम तो इस नव-उदारवादी साम्राज्यवादी विश्वीकरण के विरोधी हैं।" उनका कहना था कि विश्वीकरण को किसी भी तरह से नवउदारवादी साम्राज्यवादी विश्वीकरण की प्रक्रिया से अलग या भिन्न न किया जा सकता है,न दिखाया जा सकता है। बल्कि

देशव्यापी अभियान

1. निम्नलिखित मुद्दों पर एक स्वतंत्र तथा सघन देशव्यापी अभियान चलाया जाएगा:
   - बीमा, टेलीकोम तथा नागरिक उड्डयन क्षेत्रों के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाने के निर्णय को वापस लो।
   - सार्वजनिक क्षेत्र की उन बीमार इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए तेजी से कदम उठाओ,जिनके लाभकारी बनने की संभावना है।
   - लघु उद्योग क्षेत्र के लिए सूचीबद्ध 85 आइटमों को आरक्षणमुक्त करने के लिए निर्णय को वापस लो।
   - हड़ताल के अधिकार पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को निरस्त करने के लिए कानून बनाओ।
   - ई पी एफ पर 12 फीसद ब्याज दर बहाल करो।
   - सभी ग्रामीण तथा शहरी बेरोजगारों के लिए रोजगार सुनिश्चित करो।
   - असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाओ और घरेलू मजदूरों के लिए कानून बनाओ।
   - महिला कामगारों के लिए सभी कानूनों को सख्ती से लागू करो।
   - खेतमजदूरों के लिए सर्वसमावेशी कानून बनाओ।
   - बिजली कानून 2003 के प्रतिगामी प्रावधानों को निरस्त करते हुए उसकी समीक्षा करो।
2. उपरोक्त मुद्दों पर तमाम कार्यस्थलों पर गेट मीटिंगों, रैलियों, नुक्कड़ सभाओं आदि के जरिए 9 से 14 अगस्त तक अभियान सप्ताह मनाओ।
3. आगामी पहली सिंतबर को देशव्यापी प्रदर्शनों, रैलियों और जुलूसों आदि के जरिए "साम्राज्यवादविरोधी दिवस" मनाओ।

कामगार महिलाओं से संबंधित मुद्दे

-समान वेतन दो।

-सभी कामगार महिलाओं को मातृत्व लाभ दो।

-यौन उत्पीड़न के खिलाफ कानून बनाओ और तब तक सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों को लागू करो।

-घरेलू मजदूरों के सर्वसमावेशी कानून बनाओ।

-महिलाओं के लिए रात में काम करने पर पाबंदी को बहाल करो।

इस सिलसिले में आगामी 17 नवंबर को नयी दिल्ली में एक विशाल राष्ट्रीय कन्वेंशन का आयोजन किया जाएगा।

18-19 नवंबर को नयी दिल्ली में कामगार महिला कार्यकर्ताओं के लिए दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा।

तथाकथित अंधाधुंध खुले द्वार की नीतियों के जरिए घरेलू अर्थव्यवस्थाओं का उदारीकरण, आर्थिक पुनर्औपनिवेशीकरण के नए रूपों के जरिए विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर साम्राज्यवादी शक्तियों का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए साम्राज्यवादी विश्वीकरण के हितों को आगे बढ़ाने का मुख्य औजार बन गया है। नव-उदारवादी साम्राज्यवादी विश्वीकरण विश्व पूंजीवादी व्यवस्था की सबसे भयानक अमानवीय अभिव्यक्ति है और इसे शोषित-उत्पीड़ित जनता के संयुक्त संघर्ष के जरिए ही मात दी जा सकती है और इसे तथाकथित रूप से आवश्यक तथा अपरिवर्तनीय बता कर इसके समक्ष समर्पण करने को अंतिम हरफ नहीं माना जा सकता।

इस संदर्भ में पंधे ने नवउदारवादी विश्वीकरण की नीतियों और साथ ही साथ साम्राज्यवादी आक्रामकता तथा साजिशों के खिलाफ बढ़ते संगठित विरोध तथा विश्वव्यापी प्रतिरोध के फिनोमिना के बारे में बताया। उन्होंने इस सिलसिले में आइ एल ओ द्वारा गठित विश्वीकरण से संबंधित आयोग का भी जिक्र किया जिसकी रिपोर्ट की शुरूआत ही यह कहते हुए होती है कि "विश्वीकरण का मौजूदा रास्ता बदला जाना चाहिए... विश्व अर्थव्यवस्था के मौजूदा कामकाज में गहरे पैठे असंतुलन हैं,जो न तो नैतिक रूप से स्वीकार्य हो सकते हैं और न ही राजनीतिक रूप से दीर्घजीवी।"

तय किए गए काम

जनरल काऊंसिल ने ट्रेड यूनियन आंदोलन के फौरी मुद्दों ,जिनमें शुरूआती चरण में कामगार महिलाओं के मुद्दे भी शामिल हैं,पर स्वतंत्र अभियानों को फौरी कामों के रूप में स्वीकार किया। (देखें बाक्स) बैठक ने (16 अगस्त से शुरू होनेवाले) संसद के अगले सत्र के दौरान किसी समय संयुक्त कार्रवाई कार्यक्रमों के लिए केंद्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा विचार-विमर्श की जरूरत भी महसूस की।

इस सिलसिले में सीआइटीयू इकाइयों को इन कार्रवाइयों में जोरदार ढ़ंग से शामिल होने के लिए तैयार रहना चाहिए। बैंक, बीमा, टेलीकोम, नागरिक उड्डयन, प्रतिरक्षा और केंद्र तथा राज्य सरकार कर्मचारियों की फेडरेशनों को भी इन कार्यक्रमों में शामिल किया जाएगा।

जनरल काऊंसिल ने बी टी रणदिवे जन्मशती वर्ष में सीआइटीयू द्वारा आयोजित किए जानेवाले कार्यक्रमों पर विचार-विमर्श किया। इस सिलसिले में अगस्त तथा सितंबर महीनों में दिल्ली ,कोलकाता तथा त्रिवेंद्रम में तीन केंद्रीय ट्रेड यूनियन स्कूल आयोजित किए जा रहे हैं। बेरोजगारी के मुद्दे पर एक आंदोलन छेड़ने के लिए इस वर्ष के अंत में कभी काम के अधिकार पर एक अखिल भारतीय कन्वेंशन आयोजित करने का निर्णय भी सीआइटीयू ने लिया है। सीआइटीयू केंद्र ने विभिन्न मुद्दों पर कामरेड बी टी आर की शिक्षाओं पर पुस्तिकाओं की एक श्रृंखला प्रकाशित करना भी शुरू किया है। यह भी निर्णय लिया गया कि कामरेड बी टी आर के आगामी जन्मदिवस 19 दिसंबर 2004 को मुंबई में एक विशाल सेमिनार का आयोजन किया जाएगा।

जनरल काऊंसिल ने नयी दिल्ली में आवासीय व्यवस्था के साथ एक स्थायी ट्रेड यूनियन स्कूल तथा शोध केंद्र स्थापित करने का भी निर्णय लिया है। इसका नाम सीआइटीयू के संस्थापक महासचिव कामरेड पी राममूर्ति के नाम पर रखा जाएगा इसके निर्माण तथा दूसरे खर्चों के लिए सीआइटीयू के हर सदस्य से कम से कम एक रूपया चंदा इक्ठ्ठा किया जाएगा और दिसंबर 2004 तक यह काम पूरा हो जाएगा।

17 जुलाई 2004 को बैठक के उद्घाटन सत्र के बाद पास के ही एक हाल-कालीदास कलाकेंद्र में आम सभा हुयी ,जिसमें हजारों मजदूरों ने भाग लिया। सीआइटीयू अध्यक्ष एम के पंधे, महाराष्ट्र राज्य सीआइटीयू के क्रमश: अध्यक्ष तथा महासचिव पी सांझगिरी तथा के एल बजाज और नासिक जिला सीआइटीयू के महासचिव डी एल कराड ने इस सभा को संबोधित किया। □

सीटू प्रकाशन की नयी पुस्तक

बी टी रणदिवे

जीवन तथा शिक्षाएं

(हिन्दी तथा अंग्रेजी में अलग-अलग उपलब्ध)

लेखक : एम के पंधे

मूल्य : 10 रुपये केवल
(डाक खर्च इसके अतिरिक्त होगा)

सीआइटीयू जनरल कौंसिलः

नयी परिस्थिति तथा भूमण्डलीयकरण विरोधी संघर्ष

सीआइटीयू के ग्यारहवें महाधिवेशन के बाद की अवधि में देश के राजनीतिक परिदृश्य में अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं घट चुकी हैं। हाल ही में सम्पन्न संसदीय चुनाव इस अवधि की सबसे अधिक महत्वपूर्ण घटना हैं, इसमें संदेह नहीं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा राजस्थान में विधान सभा चुनावों के परिणामों से उत्साहित होकर भाजपा ने तेरहवीं लोक सभा को समय से पहले भंग करके आम चुनाव कराने का मन बना लिया। हमें इस बात का स्मरण फिर से करना होगा कि भाजपा की ओर से 'लोक सभा तथा राज्य विधान सभाओं के लिये पांच वर्ष की अवधि निर्धारित किये जाने' के पक्ष में तर्क दिये गए थे और संविधान की समीक्षा कराने की कार्रवाई करने पर वह तुल ही गई थी। किन्तु अब यह बात खत्म हो चुकी है और देश को चुनावी समर में कूदना पड़ गया; आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा उड़ीसा की राज्य विधान सभाओं के चुनाव भी लोक सभा चुनावों के साथ कराए गए। कुल मिला कर चुनाव परिणाम एनडीए सरकार तथा उसकी नीतियों के खिलाफ जनादेश को प्रतिबिम्बित करते हैं। दूसरी ओर यह भी एक तथ्य है कि देश भर में एनडीए के विरोधी दलों के बीच एकता नहीं थी; यदि उनमें एकता होती तो चुनावों में भाजपा का पूरी तरह सफाया हो गया होता। लोक सभा के इन चुनावों में वाम दलों के सदस्य पहले से अधिक संख्या (64) में चुने गए हैं।

चुनावों के परिणामों ने नव–उदार भूमण्डलीयकरण की नीतियों के कष्टदायक दुष्परिणामों के खिलाफ जनता के तीव्र आक्रोश को प्रतिबिम्बित किया है; एनडीए सरकार अपनी पूरी शक्ति के साथ इन नीतियों का पालन कर रही थी। इन चुनावों विशेष तौर पर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा कर्नाटक के चुनावों परिणामों का सार यही है कि जन साधारण ने आर्थिक नीतियों के कोष/बैक माडल को बुरी तरह ठुकरा दिया है क्योंकि यह माडल अमीरों को और अमीर बनाता है तथा जन साधारण के लिये रोजगारहीनता, घोर दरिद्रता तथा वंचना की स्थिति लाने वाला है। इन परिणामों ने साम्प्रदायिक शक्तियों के लिये जनता में बढ़ रहे प्रतिकार को भी व्यक्त किया है। हड़ताल के अधिकार की रक्षा के लिये 24 फरवरी को देश व्यापी हड़ताल की गई थी; इस हड़ताल ने भी चुनाव अभियान में निर्णायक भूमिका निभाई है।

चुनावों के बाद का परिदृश्य

अब चुनावों के बाद देश का जो राजनीतिक परिदृश्य बना है, उसे देखते हुए हमें मौजूदा स्थिति की वस्तुपरक समीक्षा करनी होगी और अपने भावी संघर्षों का कार्यक्रम बनाना होगा। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) की ओर से बनाए गए सांझे न्यूनतम कार्यक्रम को क्योंकि नयी सरकार ने अपना लिया है फिर भी उसकी आर्थिक नीतियों की सत्ता की बुनियादी दिशा में कोई बदलाव नहीं आया है। यद्यपि उसमें कुछ सकारात्मक रुझान देखने को मिले हैं और 'खेतिहर श्रमिकों को संरक्षण देने,' 'ग्रामीण परिवारों को वर्ष में कम से कम 100 दिनों के लिये रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी', 'सभी खेतिहर श्रमिकों के लिये सर्वसमावेशी संरक्षणात्मक कानून बनाने और उनके लिये न्यूनतम वेतन सम्बन्धी कानूनों को पूरी तरह लागू करने', 'कृषि के क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश बढ़ाने', 'हायर एण्ड फायर के विचार को रद्द किये जाने', 'निजीकरण के प्रश्न पर मामला दर मामला विचार किये जाने', 'सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रमों को सार्वजनिक क्षेत्र में ही रहने देने' जैसे सद्भावना से प्रेरित वक्तव्य भी दिये गए है।

हमें यह भी उल्लेख करना होगा कि चुनाव परिणामों की घोषणा हो जाने के तत्काल बाद अनेक कांग्रेस नेताओं और उनके साथ–साथ दूसरे दलों के नेताओं की ओर से ऐसे वक्तव्य दिये गए जिनमें सुधारों के प्रति उनका प्रेम स्पष्ट झलक रहा था और उन्होंने तथा कथित 'आर्थिक सुधारों' को जारी रखे जाने के लिये अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की थी। यह बात भी ध्यान में रखे जाने की जरूरत है कि यूपीए के सभी घटक सुधारों के पक्षधर हैं। दिल्ली और मुम्बई के हवाई अड्डों के निजीकरण के लिये वर्तमान में जारी प्रयासों को भी हमें अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देना चाहिये जबकि सांझे न्यूनतम कार्यक्रम में इसके लिये कोई प्रतिबद्धता व्यक्त नहीं की गई थी। इस प्रकार की परिस्थितियों में यदि उदारीकृत नीति की सत्ता बनी रहती है तो सीएमपी में किये गए वादे बस वादे ही बन कर रह जाएंगे।

वर्तमान परिस्थितियों में श्रमिक आंदोलन को भाजपा के नेतश्त्व वाली साम्प्रदायिक शक्तियों को और अधिक अलग–थलग किये जाने की जरूरत को ध्यान में रखते हुए अपने संघर्ष के भावी कार्यक्रम का निर्धारण करना होगा। इसके साथ ही जन साधारण की आजीविका तथा अधिकारों की रक्षा के लिये श्रमिक वर्ग को लामबंद भी करना होगा। एनडीए सरकार की पराजय ने मेहनतकश लोगों में भारी आशाओं को जन्म दिया है; ये वही लोग हैं जिन्होंने उसके शासनकाल में अपने अधिकारों तथा आजीविका पर हमलों के खिलाफ कड़ा संघर्ष किया था। हमें इन अपेक्षाओं के पक्ष में जोरदार आवाज उठानी होगी; उसके लिये पूरी शक्ति के साथ अभियान चलाना होगा तथा जन लामबंदी करनी होगी। हमें मांग करनी होगी कि आर्थिक नीतियों को जन मुखी बनाया जाए तथा जनवादी अधिकारों का विस्तार किया जाए; अन्यथा लोग हतोत्साहित होने लग जाएंगे और इसका लाभ साम्प्रदायिक शक्तियों की ओर से उठाया जाएगा जो पहले ही इस ताक में बैठी हुई हैं। लोगों को इस दिशा में लामबंद किये जाने का दायित्व श्रमिक वर्ग को अपने कंधों पर लेना होगा; साम्प्रदायिक ताकतों को और अधिक अलग–थलग करना उसके राजनीतिक कार्य का अभिन्न अंग है; इसके साथ ही उसे वामपक्ष के हस्तक्षेप में सहायता देना तथा उसे मजबूत बनाने का काम करना होगा; उसे यकीनी बनाना होगा कि केन्द्र की सरकार लोगों के लिये काम करे। श्रमिक वर्ग की ओर से तश्णमूल स्तर पर की गई लामबंदी नीति सम्बन्धी मामलों में वाम दलों के हस्तक्षेप को और अधिक प्रभावी बनाएगी। देश में धर्म निरपेक्ष शासन को बनाए रखने और साम्प्रदायिक शक्तियों को अलग–थलग किये जाने के लिये इस प्रकार का हस्तक्षेप न केवल निर्णायक बल्कि अनिवार्य भी है। इसके साथ–साथ हमें साम्प्रदायिक शक्तियों के खिलाफ अलग से भी प्रचार अभियान चलाना होगा। हमें मांग करनी होगी कि सरकार की ओर से प्रशासन तथा विभिन्न शैक्षणिक, सामाजिक तथा

सांस्कृतिक संस्थानों को भगवाकरण के विषाणुओं से मुक्त करने के लिये ठोस एवं कड़े कदम उठाए जाएं।

हमारे कार्य तथा हमारी जिम्मेदारियां

भाजपा के नेतश्त्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक जनतांत्रिक गठबंधन की पराजय देश की धर्म निर्पेक्ष शक्तियों तथा भारत के संविधान में समाहित धर्म निरपेक्षता के सिद्धांतों की विजय है। सीआइटीयू दूसरी सभी धर्म निरपेक्ष ताकतों के साथ मिल कर साम्प्रदायिक ताकतों की पराजय पर संतोष का अनुभव करता है। किन्तु हम इस कहावत का उल्लेख जरूर करेंगे कि साम्प्रदायिक शक्तियां धाराशायी तो हुई हैं पर खत्म नहीं हुई। इसलिये साम्प्रदायिकता के खिलाफ हमारी जंग आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना पहले थी।

हमें यह शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये कि साम्प्रदायिकता के खिलाफ संघर्ष की अपनी विशेषताएं होती हैं; आर्थिक मांगों को लेकर चलाए गए संघर्षों की साम्प्रदायिकता के खिलाफ जंग में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। श्रमिक आंदोलन के सामने इस समय सबसे बड़ा काम हर सम्भव ढंग तरीके से श्रमिकों के मन मस्तिष्क पर छाए साम्प्रदायिक विचारों तथा भावनाओं का उन्मूलन करना है।

वर्तमान स्थिति सीआइटीयू के कंधों पर भारी भरकम जिम्मेदारियों का बोझ डालने वाली है। संसदीय चुनावों में भाजपा गठबंधन की पराजय तथा उसके स्थान पर केन्द्र में यूपीए सरकार जिसे वामपक्षी दल बाहर रह कर समर्थन दे रहे हैं, का गठन हो जाने के फलस्वरूप मेहनतकश अवाम में भारी आशाओं ने जन्म ले लिया है। कांग्रेस के नेतश्त्व वाले सत्ता–धारी गठबंधन के वर्गीय चरित्र तथा रुझानों को देखते हुए कहा जा सकता है कि यह गठबंधन उदारीकृत नीति की सत्ता को बरकरार रखना चाहता है। इस बात की सम्भावना नहीं है कि लोगों की अपेक्षाओं जो चुनावी जनादेश में प्रतिबिम्बित हुई थीं, का सकारात्मक प्रत्युत्तर दिया जाएगा; भले ही यह सरकार अपने शासन को बनाए रखने के लिये वाम दलों पर निर्भर क्यों न करती हो। नयी सरकार राष्ट्रीय न्यूनतम सांझा कार्यक्रम में दर्ज अनेक जन पक्षीय प्रतिबद्धताओं को किस सीमा तक कार्यरूप देती है; हमें इस पर निगरानी रखनी होगी। वित्त मंत्री पी चिदाम्बरम की ओर से हाल ही में प्रस्तुत 2004–05 के बजट में भले कुछ सकारात्मक कार्रवाईयां किये जाने के संकेत मिलते हैं; वे इन्हें कहां तक कार्यान्वित करेंगे, यह देखना अभी बाकी है। इस पश्ष्ठभूमि में, श्रमिक आंदोलन को शक्तिशाली देशव्यापी लामबंदी, अभियान एवं आंदोलन चला कर जहां सांझे न्यूनतम कार्यक्रम की जन पक्षीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की मांग करनी होगी वहीं आर्थिक नीतियों की दिशा को बदलने पर भी बल देना होगा; इस प्रकार उसे जनता की अपेक्षाओं पर पूरा उतरने के लिये अपने कर्त्तव्यों का निवर्हन करना होगा।

इस पृष्ठभूमि में, सीआइटीयू को सुनिश्चित बनाना होगा कि साम्प्रदायिक शक्तियां विनाशकारी उदारीकृत नीति की सत्ता के विरोध पक्ष की भूमिका को हथिया न लें; उसे अत्यंत सजग होकर साम्प्रदायिक शक्तियों की कार्रवाईयों पर नजर रखनी होगी।

इस संदर्भ में, हमें संघर्ष के कार्यक्रमों के लिये सीधा एवं स्पष्ट रुख अपनाने के मामले में श्रमिक आंदोलन में हमारे सहयोगियों की ओर से दिखाए जा रहे ढिलमुलपन एवं हिचकिचाहट से भी प्रभावी ढंग से निपटना होगा। यद्यपि 24 फरवरी की राष्ट्रव्यापी हड़ताल ने श्रमिक आंदोलन की एकता को नये आयाम दिये हैं और समय की कसौटी पर खरी उतरी इस सच्चाई को पुनः दोहराया है: "संघर्ष के लिये श्रमिक वर्ग की एकता तथा इसका निर्माण केवल संघर्ष के द्वारा हो सकता है" और तृणमूल स्तर पर संघर्ष तथा एकता के लिये यह ललक आगामी संघर्षों में श्रमिक आंदोलन की ठोस एकता को चिरस्थायी तथा यकीनी बना सकती है। यह श्रमिक वर्ग के संयुक्त संघर्ष की कार्रवाई थी किन्तु इसके लिये सभी श्रमिक संगठनों की एकता नहीं थी। श्रमिक आंदोलन में सभी श्रमिक संगठनों की एकता एक रणनीतिक नारा है; इसका उद्देश्य है सम्पूर्ण श्रमिक वर्ग को संगठित करना। किन्तु व्यवहार में, इन नारे को संघर्ष के विभिन्न चरणों में से गुजर कर ही अमल में उतारा जा सकता है। जहां हम अपनी श्रेणी को सम्पूर्ण रूप में एकताबद्ध करने की कोशिशें करते हैं वहीं हम इन सभी वर्षों में अर्जित की गई अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने और अपनी नियत भूमिका निर्वहन करने के लिये संघर्ष चलाने के मामले में किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं कर सकते।

हमें इस काम के लिये स्वयं को विचारधारात्मक तथा संगठनात्मक दोनों तरह से तैयार करना होगा। हमें प्रकट रूप में या दूसरे किसी भी रूप में किसी भी स्तर पर नव–उदार आर्थिक नीतियों के प्रति अपने दृढ़ विरोध को जारी रखना होगा और इसे यकीनी बनाना होगा। इस दिशा में आगे बढ़ने के लिये हमें उदारीकरण विरोधी संघर्ष के मंचों जैसे भारत के श्रमिक संघों की प्रायोजन समिति तथा राष्ट्रीय जन संगठन मंच (एनपीएमओ) को फिर से सक्रिय एवं मजबूत बनाने के कामों को प्राथमिकता देनी होगी। हमारे कुछ सहयोगी संगठनों ने इस सम्बन्ध में उदासीन रुख अपना रखा है; इसका उल्लेख हम पहले ही कर चुके हैं। हमें धैर्य पूर्वक इस प्रकार के रुझान का प्रतिकार करना होगा और भूमण्डलीयकरण की नीतियों के खिलाफ संघर्ष के धर्म निरपेक्ष एवं संयुक्त मंच के नाभिकीय केन्द्र के रूप में प्रायोजन समिति तथा एनपीएमओ को केन्द्र में लाने के लिये जी तोड़ प्रयास करने होंगे।

इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि सीआइटीयू यूनियनों तथा हमारे भ्रातश श्रमिक संघों एवं जन संगठनों द्वारा हमारे काम के प्रति संयुक्त समझ के साथ अधिकाधिक लामबंदी तथा अधिकाधिक पहलकदमी को सुनिश्चित एवं सक्रिय बनाया जाए।

अनेक कमजोरियां होने पर भी हमारे देश में श्रमिक आंदोलन केन्द्र में सरकार को बदलने के बारे में सफलतापूर्वक अपनी भूमिका का निर्वहन कर सका है और वह साम्प्रदायिक ताकतों को सत्ता से निकाल बाहर करने में सफल हो सका है। नयी स्थिति में भी भूमण्डलीयकरण विरोधी संघर्ष के लिये इस प्रकार के जोरदार प्रयास किये जाने की जरूरत किसी भी प्रकार से कम नहीं होती; इसकी अपेक्षा यह केवल संयुक्त संघर्षों को तेज करने की आवश्यकता को ही फिर से दोहराती है। वर्तमान स्थिति के गर्भ में हमारे संघर्षों को और आगे बढ़ाने तथा प्रभावी राजनीतिक हस्तक्षेप के लिये श्रमिक आंदोलन की क्षमता का निर्माण किये जाने की अपार सम्भावनाएं विद्यमान हैं। हमें आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिये अपनी उपलब्धियों की रक्षा करनी होगी तथा संघर्षों को और आगे ले जाना होगा। सीआइटीयू समितियों तथा इकाईयों को सभी स्तरों पर खुद को सांगठनिक एवं विचाराधारात्मक रूप से खुद को तैयार करना होगा और इस दिशा में बड़ी तेजी के साथ पहलकदमियां करनी होंगी।

(जनरल कौंसिल की बैठक में प्रस्तुत महासचिव की रिपोर्ट के प्रमुख अंश)